जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 213 प्रभात कोटा, रविवार 18 मई, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अब सिंधियों ने अलग ''सिंधु देश'' की माँग जोरों से उठाई पाकिस्तान में

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अब काफी मुखर व साहसी हो गये हैं, सिंधु देश की माँग को लेकर चल रहे आंदोलन, प्रदर्शन की ''क्लिप'' दिखाने में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मई। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी स्वतंत्रता की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान के हैदराबाद को उत्तरी शहरों से जोड़ने वाले राजमार्ग को सिंधी प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया और ''सिंधु देश'' के नारे लगाते हुए पाकिस्तान की संघीय सरकार के खिलाफ धरना दिया।

सिंध के लोग अब अपनी अलग पहचान और अपनी भूमि को लेकर बेहद समर्पित और मुखर रूप से सामने आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अब काफी मुखर व साहसी हो गए हैं, सिंधु देश की मांग को लेकर चल रहे, आंदोलन व प्रदर्शनों की क्लिप्स दिखाने में। ये क्लिप्स पूरे देश या प्रांतों में हो रहे प्रदर्शनों और रैलियों को दिखा रही हैं। सिंध प्रांत का हैदराबाद शहर अब सिंधी विरोध और स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केन्द्र बनता जा रहा है।

इन नारों की गूंज दक्षिणी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सुनाई दे रही है। सिंधी प्रदर्शनकारी, पंजाबियों द्वारा उनके क्षेत्र की ज़मीनों पर किए जा रहे कथित कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कराची को सरकार पहले ही संघीय क्षेत्र घोषित कर चुकी है, जिसका सिंधी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं।

- सिंधी लोग मुख्य रूप से, पाकिस्तान के प्रशासन में पंजाबियों का भारी ''आधिपत्य'' सा होने से परेशान हैं। पंजाब व सिंध के बीच इस मसले पर विवाद व कटुता कई सालों से चल रही है।
- अब सिंध के लोग इस ''आधिपत्य'' को समाप्त करने के लिये मानसिक रूप से काफी समय से तैयार हैं तथा अपने अलग स्वतंत्र राज्य की माँग कर रहे हैं।
- बलूचिस्तान के ''स्वतंत्रता'' आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर सिंध की जनता भी अपने अलग ''देश'' की माँग पुरजोर ढंग से उठा रही है और माँग की पूर्ति के लिये, किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

सिंधी मूलत: उद्यमशील हैं और व्यापार में सफल रहे हैं और कराची पाकिस्तान का प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र है। लेकिन, पंजाबी वर्चस्व के कारण सिंधियों को सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान सरकार में पंजाबी वर्चस्व बनाए रखने के कारण यह स्थिति बनी है।

सिंधी लोग, पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासन में पंजाबियों के प्रभुत्व के विरुद्ध है। वे इस प्रभुत्व को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और सिंध की आज़ादी की मांग को खुलकर उठा रहे हैं। पंजाब और सिंध के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो अब और भी गहराता जा रहा है।

बलूचिस्तान में जो हो रहा है, उसे देखकर सिंधी भी अब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस सप्ताह बलूचों के एक कट्टरपंथी धड़े ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और संघीय सरकार व सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक हमले तेज़ कर दिए हैं।

बलूचों के उदाहरण से सिंधियों को हिम्मत मिली है और वे भी अब खुलकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे हैं। हालांकि, यह मांग वर्षों से दबे स्वर में चल रही थी, लेकिन, अब जब संघीय सरकार का नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है है तो क्षेत्रीय और पृथकतावादी ताकतें अधिक मुखर हो गई हैं तथा आशावादी महसूस कर रही हैं।

पाकिस्तान की सरकार ने यदा-कदा होने वाले विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाया था। कई आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया और कई राष्ट्रवादी नेता लापता हो गए, जिनका कोई सुराग नहीं मिला है। अब यूट्यूब चैनल्स पर राष्ट्रवादी सिंधियों की रिहाई की मांग और गुमशुदा लोगों की जानकारी साझा की जा रही है। पाकिस्तान राज्य द्वारा अमानवीय यातना देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जनता इसके खिलाफ हथियार उठाने को तैयार दिख रही है। अन्य प्रांतों के मुकाबले सिंध अपेक्षाकृत शांतिप्रिय प्रांत रहा है और वहाँ हिंसा की घटनाएं सीमित रही हैं। लेकिन सरकार और पुलिस की हिंसा के कारण प्रदर्शन और भी उग्र होते जा रहे हैं। सरकार की नीतियां अब उल्टा असर डाल रही हैं और उग्र आंदोलन की ज़मीन तैयार कर रही हैं। भारत द्वारा पश्चिमी सिंधु नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने से पाकिस्तान में जल-संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है और पंजाबी-सिंधी संघर्ष और कटु हो सकता है। पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में अब पंजाबी वर्चस्व को सहन करने की सहनशीलता नहीं बची है और अलग-अलग हिस्से इस दमनकारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर दिख रहे हैं।

हाई कोर्ट ने पेपर लीक केस में जमानत याचिकायें खारिज कीं

जयपुर, 17 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 का पेपर लीक करने वाले तुलछाराम और नकल कर परीक्षा पास करने वाली मंजू भामू की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजकीय सेवा के लिए अभ्यर्थी दिन रात मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। पेपर लीक से उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। वहीं, इन दिनों नकल के मामले काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों को

- आरोपी तुलछाराम पर, महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 का पेपर लीक करने का और मंजू भामू पर नकल करके परीक्षा पास करने का आरोप है।

जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

मंजू भामू की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया कि उससे किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है। वहीं, उसे गिरफ्तारी का आधार तक नहीं बताया गया। वह गत 19 फरवरी से जेल में बंद है, जिससे चलते उसकी तीन साल की बच्ची की परवरिश प्रभावित हो रही है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। तुलछाराम की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अधिकांश में वह दोषमुक्त हो चुका है और कई मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है। उसके खिलाफ जांच पूरी कर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस पार्टी की ''चॉयस'' से परेशान है आम कार्यकर्ता व नेता

जैसा कि विदित ही है, एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल विश्व के पाँच महत्वपूर्ण और बड़े देशों की राजधानी जायेगा तथा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन देशों की सरकारों को विस्तृत जानकारी देगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मई। राहुल गांधी ने अपने चारों ओर ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, जो पार्टी के हित में नहीं सोचते, बल्कि अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने, निजी हिसाब-किताब चुकता करने और इस प्रक्रिया में पार्टी के सक्षम लोगों को बाहर निकालने की राजनीति में लगे हैं।

इसका एक उदाहरण शशि थरूर हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख नियुक्त किया है, जो दुनिया के पाँच प्रमुख देशों की राजधानियों में जाकर पाकिस्तान, आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर आदि पर जानकारी देगा।

चूंकि वे विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को उनका नाम सरकार को भेजना चाहिए था।

लेकिन नहीं, पार्टी के नेता पार्टी के भीतर ही एक अलग किस्म का युद्ध लड़ रहे हैं।

कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि जब सरकार ने चार नाम मांगे थे, तब कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं भेजा।

- मोदी सरकार ने शशि थरुर को इस प्रतिनिधि मण्डल का नेता बनाया है। पर, कांग्रेस ने थरुर का नाम नहीं भेजा है, प्रतिनिधिमण्डल में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने के लिये।
- कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की लिस्ट में कई नाम और भी चौंकाने वाले हैं, जैसे, राजा बरार का नाम कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी को पच नहीं रहा।
- एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि, माना जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं, पार्टी द्वारा मनोनीत सदस्यों का नाम फाइनल करने में। पर, राजा बरार, जिसका भारत की विदेश नीति से दूर-दूर का संबंध नहीं रहा, उनका नाम प्रतिनिधिमण्डल में शामिल करने के लिये भेजना बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। जबकि, मनीष तिवारी का नाम क्यों कटा, इसकी वजह भी किसी को समझ नहीं आ रही।

लेकिन सरकार ने उन्हें कांग्रेस की ओर से नामित करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख बना दिया।

अब कांग्रेस खुद को बेहद हास्यास्पद स्थिति में पा रही हैऔर इसके पीछे है वेणुगोपाल और जयराम रमेश की आपसी राजनीति। अब जब थरुर का नाम सरकार की तरफ से आ गया है तो वे मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं हैं।

अब राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या पार्टी में ''योग्यता के लिए कोटा'' भी तय किया जाना चाहिए।

जाति का ध्यान रखना ठीक है, लेकिन राजा बरार? क्या वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एबीसीडी भी समझते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आनन्द शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सैय्यद नासिर व राजा बरार, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान से भारत में की जाने वाली आतंकी घटनाओं के संबंध में भारत का पक्ष रखने के लिए अन्य देशों की यात्रा पर जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के लिए कांग्रेस ने चार सांसदों के नाम दे दिए हैं।

सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में रमेश ने बताया कि शुक्रवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात की थी। कांग्रेस से कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे प्रतिनिधिमंडल के लिए कांग्रेस चार नाम दे।

- थरुर का नाम जब कांग्रेस की तरफ से नहीं आया तो संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू ने भारत सरकार की ओर से शशि थरुर का नाम जोड़ा, उस सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल की लिस्ट में, जो पाँच देशों की यात्रा करेगा, पाकिस्तान व आतंकवादियों के संबंधों को अच्छी तरह से उजागर करने के लिये।

शुक्रवार दोपहर लोकसभा में विपक्ष के नेता के चार नाम दिए जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे, इनमें पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, राज्यसभा सांसद सय्यद नासिर हुसैन और लोकसभा सांसद राजा ब्रार शामिल हैं।

आश्चर्य की बात है कि इसमें तिरुवनन्तपुरम के सांसद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरुर का नाम नहीं है।

मंत्री किरण रिजीजू ने हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विश्व को ब्रीफ करने वाले सात सांसदों की लिस्ट में शशि थरुर को शामिल किया है, जो विश्व को भारत के आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरैंस की नीति का संदेश देंगे।

यू ट्यूबर ज्योति पाक जासूस निकली

हिसार, 17 मई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 15 मई को

- हरियाणा पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है।

उपाधीक्षक जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से गिरफ्तार किया। खुफिया ब्यूरो की टीम ज्योति से पूछताछ कर रही है। हिसार पुलिस के मुताबिक, ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। वह सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायाधीश बेला त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट से विदाई कई वर्षों तक चर्चित रहेगी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने परम्परागत विदाई समारोह व विदाई भोज का बहिष्कार किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने 16 मई 2025 को सेवा निवृत्त हो गईं, लेकिन बेहद अप्रत्याशित अंदाज में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से उन्हें कोई औपचारिक विदाई नहीं दी गई। यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा का स्पष्ट उल्लंघन था, जो न्यायपालिका और वकीलों, विशेष रूप से दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों, के बीच तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है।

हालांकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उनके कई सहयोगियों ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी के योगदान की प्रशंसा की, लेकिन

- एसोसिएशन की शिकायत ये थी कि न्यायाधीश बेला त्रिवेदी का रुख काफी कुछ सरकार में झुकाव रखता था तथा इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों-अधिकारियों के साथ उनके मतभेद न्यायालय में भी सार्वजनिक रूप से देखे गये थे।
- न्यायाधीश बेला त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति व नियुक्ति पाने से पहले गुजरात हाई कोर्ट में जज थीं, उसी समय जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मु.मंत्री थे।

बार एसोसिएशन और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के एक वर्ग की ओर से ठंडी प्रतिक्रिया ने उनके कार्यकाल के दौरान रहे विवादों को रेखांकित किया। कई अधिवक्ताओं ने, जिन्होंने मानवाधिकारों और जनहित से जुड़ी अहम याचिकाएं जस्टिस त्रिवेदी की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की थीं, उन्होंने न्याय दिए जाने को लेकर उनकी कार्यशैली पर गंभीर आपत्तियाँ जताईं।

एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा,

''कोई भी न्यायाधीश, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता या सत्ता के प्रभाव में आता है, उसे न्यायपालिका के इतिहास में अच्छी यादों के साथ नहीं देखा जाएगा।'' उनकी बात से सहमति जताते हुए एक और प्रख्यात वकील ने, न्यायमूर्ति त्रिवेदी को औपचारिक सम्मान न दिए जाने पर खेद प्रकट करते हुए कहा,''उनके ऊपर जो लोग सत्ता की सीढ़ियों पर बैठे हैं, वे भी न्यायिक मानकों के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं।''

गुजरात से ताल्लुक रखने वाली न्यायमूर्ति त्रिवेदी को मौजूदा सत्तारुढ़ पार्टी के निकट माना गया। उनके कार्यकाल के दौरान उनके कई फैसले विवादास्पद रहे और कई बार सुप्रीम कोर्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप के 15 पार्षदों ने पार्टी छोड़ी

नयी दिल्ली, 17 मई। आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत्व से नाराज 15 निगम पार्षदों ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

आप के वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने कहा, हमारे 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और अलग दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है। पिछले ढ ाई साल में हम लोगों के काम नहीं कर पाये। हमारा पूरा समय लड़ाई-झगड़े में बीता है। पार्षदों के इस्तीफे में कहा गया है कि हम सभी निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम में वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी के

- इन्हें शिकायत है कि पार्टी में इतना लड़ाई झगड़ा है कि वे जनता के काम नहीं कर पाए।

टिकट से चुने गये थे, लेकिन 2022 में दिल्ली नगर निगम में सत्ता में आने के बावजूद, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निगम को सुचारु रूप से चलाने में असमर्थ रहा। शीर्ष नेतृत्व का निगम पार्षदों से आपस में समन्वय न के बराबर रहा, जिसके कारण पार्टी विपक्ष में आ गयी।

पार्टी से इस्तीफा देने वालों में गोयल के अलावा, हेमचंद्र गोयल, हिमानी जैन, ऊषा शर्मा, अशोक पांडेय, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार, अनिल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने सातवीं बार फिर दावा किया कि व्यापार बंद करने की धमकी देकर भारत-पाक युद्ध में ''सीज़फायर'' करवाया

इंग्लैण्ड के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने, ट्रंप के इस दावे की परोक्ष पुष्टि की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मई। अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के युद्धविराम के दावे की पुष्टि के एक और प्रयास के अन्तर्गत, ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा है कि ब्रिटेन, अमेरिका के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच ''स्थायी संघर्ष विराम,'' ''संवाद'' और ''विश्वास बहाल करने के उपायों'' पर काम कर रहा है।

लैमी ने अपनी पाकिस्तान की दो दिन की यात्रा के अन्त में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ''रायटर्स'' को बताया, ''हम अमेरिका के साथ काम करते रहेंगे, ताकि एक स्थायी युद्धविराम को बढ़ावा मिले। हम भारत और पाकिस्तान के साथ भी काम करेंगे, ताकि दोनों पक्षों के बीच विश्वास पैदा करने वाले उपाय किए जा सकें।

जब उनसे भारत द्वारा सिंधु जल समझौते के निलम्बन, जिससे पाकिस्तान की जल-आपूर्ति बहुत कम हो गई है, के बारे में पूछा गया, तो लैमी ने कहा, ''हम सभी पक्षों से आग्रह करेंगे कि वे संधि के अपने कर्तव्यों को पूरा करें।''

नई दिल्ली ने पिछले महीने कहा था कि उसने 1960 के समझौते, जो सिन्धु नदी-तंत्र के उपयोग को नियन्त्रित करता है, की सहभागिता ''निलम्बित'' कर दी है। यह एक ऐसी कार्यवाही है, जिसके बारे में पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत कृषि पर निर्भर देश (पाकिस्तान) की जल-आपूर्ति को अवरुद्ध करेगा, तो वह इसे युद्ध की कार्यवाही मानेगा।

लैमी ने कहा कि ब्रिटेन भी ''आतंकवाद'' को रोकने के बारे में पाकिस्तान से बात करना जारी रखेगा।

- पाकिस्तान तो शुरु से यह ही कह रहा है कि अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों, जिनमें इंगलैण्ड भी शामिल है, ने भारी भूमिका निभाई, न्यूक्लियर हथियारों से सुसज्जित देशों, भारत-पाक के बीच ''सीज़फायर'' कराने में।
- दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना रवैया पुनः स्पष्ट किया कि भारत-पाक के बीच कश्मीर का विवाद एक आपसी मामला है, जिसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका न पहले थी, न अब है और न कभी होगी।
- प्रवक्ता ने यह भी कहा, दोनों देशों के बीच एक ही मुद्दा है, पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर को कैसे खाली करवाया जाये।

उन्होंने कहा कि यह (आतंकवाद) इस देश, इसकी जनता तथा इस क्षेत्र के लिये घोर अभिशाप'' है।

लैमी ने कहा, ''ये दो ऐसे पड़ोसी हैं, जिनका एक लम्बा इतिहास है, लेकिन ये दो ऐसे पड़ोसी भी हैं, जिन्होंने हालिया समय में आपस में शायद ही कभी बात भी की हो, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे (इस तनाव में) वृद्धि न हो तथा युद्धविराम की स्थिति बनी रहे।''

लैमी की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सातवीं बार यह दावा किया है कि वे दिल्ली और इस्लामाबाद को अमेरिकन व्यापार की पेशकश करके न्यूक्लियर युद्ध के कगार से पीछे खींचकर लाये हैं।

भारत का कहना है कि इस समय पाकिस्तान के साथ जो स्थिति है, वह द्विपक्षीय ''समझबूझ'' है, युद्धविराम नहीं। दिल्ली ने मध्यस्थता के किसी भी सुझाव /प्रस्ताव को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया है।

मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की ''लम्बे समय से चली आ रही राष्ट्रीय स्थिति (सोच), कि जम्मू-कश्मीर के मसले भारत और पाकिस्तान के बीच के द्विपक्षीय मामले हैं, में कोई बदलाव नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा बार-बार किये जा रहे इन दावों को अमान्य सिद्ध करने की कोशिश की कि वॉशिंगटन ने मध्यस्थता की है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ट्रंप के इस दावे के बारे में पूछा गया कि अमेरकन ने यह धमकी दी थी कि अगर भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर गोलीबारी जारी रखी, तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार रोक देगा। इस प्रश्न के उत्तर में जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर शुरु होने के बाद, वॉशिंगटन के साथ हुई किसी भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वैटिकन सिटी जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 17मई। भारत सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल वेटिकन सिटी में 18 मई को होने वाले पोप लियो चौदहवे के अधिष्ठापन समारोह में भाग लेगा। इसमें राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड

- राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड के डिप्टी सी.एम. यथुंगो पैटन का प्रतिनिधिमंडल पोप लियो चौदहवें के अधिष्ठापन समारोह में शामिल होगा।

के उपमुख्यमंत्री यंथुंगो पैटन शामिल हैं।

यहां जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस महत्वपूर्ण वैश्विक धार्मिक आयोजन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी अंतर-धार्मिक जुड़ाव, समुदायों के बीच परस्पर सम्मान को दर्शाती है।